www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 25 || लखनऊ
शनिवार
25 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:33
सूर्यास्तः 06:36
अधिकतमः 43°00
न्यूनतमः 28°00

पेज 03

विशेष समाचार
हाल ही में, मणिपुर में वाई. खेमचंद... >> पेज 02
चौपालों से गूंजा लोकतंत्र... >>पेज 04
'मैं काफी अनकम्फर्टेबल थी'...

राघव चड्ढा के नेतृत्व में दो-तिहाई राज्यसभा सांसदों का बड़ा फैसला, दलबदल कानून से बचने का दावा

‘आप’ से छूटा सात का साथ

दिनकर जी ने जातियों पर प्रहार किया

योगी ने कविताएं पढ़कर पर्चियां जेब में रखीं

- सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर के सौपौत्र को किया सम्मानित।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविताओं के जरिए जातियों पर प्रहार किया। मैं उनकी पंक्तियों से विरोधियों पर प्रहार करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मिरथी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित 3 दिन के रश्मिरथी पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने दिनकर की पंक्तियां पढ़ीं।

उसके बाद पंक्तियां लिखीं पर्चियां जेब में रख लीं। दिनकर के पोते को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा- दिनकर के शब्द अनमोल हैं। उनकी रचनाएं हमेशा पढ़ी जाती रहेंगी। दिनकर की वाणी पर सरस्वती का वास था। इस दौरान रश्मिरथी महाकाव्य पर आधारित नाटक का मंचन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा।

ऐलान

तमसा संकेत, एजेंसी

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल होंगे। इसका ऐलान पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल, राजेंदर गुप्ता हमारे साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। अशोक मित्तल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और जालंधर में उनके घर 10 दिन पहले (15 अप्रैल) ED ने छापेमारी की थी। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी जॉइन की। बाकी चार सांसद अभी सामने नहीं आए हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा- मैं इटानगर में हूं। शाम को दिल्ली लौटकर बात करूंगी। पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- इन लोगों ने आज हमारी पार्टी के सांसदों को तोड़ा। ये वही वॉशिंग मशीन है, जो शरद पवार की पार्टी तोड़ने में इस्तेमाल की गई थी। पंजाबी जब प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, जब उनसे धोखा किया जाता है तो पंजाबी जो करते हैं उन्हें कई पीढ़ियां याद रखती हैं। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जब पार्टी के “मेन आर्किटेक्ट” ने ही साथ छोड़ दिया, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए।

राघव बोले- दलबदल कानून नहीं लगेगा

राघव ने बताया कि पार्टी के दो-तिहाई सांसदों ने यह फैसला लिया। इसलिए दलबदल कानून लगने का कोई मतलब नहीं है। राघव चड्ढा ने कहा पिछले कुछ सालों से, मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। हमने यह फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को BJP में मिला लेंगे।

भगवंत मान बोले- ये वही वॉशिंग मशीन, जिससे पवार की पार्टी तोड़ी

पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले- इन लोगों ने आज हमारी पार्टी के सांसदों को तोड़ा। ये वही वॉशिंग मशीन है, जो शरद पवार की पार्टी तोड़ने में इस्तेमाल की गई थी। पंजाबी जब प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, जब उनसे धोखा किया जाता है तो पंजाबी जो करते हैं उन्हें कई पीढ़ियां याद रखती हैं।

पंजाब सीएम बोले- राघव सरपंच बनने लायक नहीं थे

सीएम भगवंत मान ने कहा कि राघव का यहां दम घुटने लग गया। जब 50 नंबर कोठी में थे, तो वहां पर बड़ी खुली हवा आती थी। साइकिल का भी स्टैंड होता है। कहीं तो खड़े हो जाओ। वैसे तो यह सरपंच बनने लायक नहीं थे। अशोक मित्तल के यहां ईडी का एक छापा था। इनकी पार्टी ईडी और सीबीआई के सिर पर चलती है। यह डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी के साथ लोग खड़े हैं।

हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। सात लोग पार्टी नहीं थे। कई बार व्यक्ति को बहम हो जाता है कि सेल्यूट हमें मारे जाते है। लेकिन पीछे कोई और होता है। पंजाब के लोग इन गद्दारों को माफ नहीं करेंगे।

राघव चड्ढा के बीजेपी के खिलाफ 3 बयान

- **31 जुलाई 2023:** दिल्ली ऑर्डिनेंस/बिल पर कहा- अलोकतांत्रिक और अवैध, दिल्ली की जनता पर BJP के हमले का चरम है। यह बिल चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देगा और जनता के जनादेश का अपमान है। यह भाजपा की दिल्ली सरकार को खत्म करने की साजिश है।
- **23 जुलाई 2023:** दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल असंवैधानिक है, संविधान बचाइए। केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने का आरोप लगाते हुए राज्यसभा चेयरमैन को पत्र लिखकर कहा था- बिल असंवैधानिक है, संविधान बचाइए।
- **1 अगस्त 2023:** बिल डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी बना देगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर ही कहा था बिल डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी बना देगा। मतलब, जनता की सरकार की जगह अफसर-शाही हावी हो जाएगी।

राघव ने 2 साल पहले दिए थे अलगाव के संकेत

- 21 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले जब शराब घोटाले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। तब राघव ने न कुछ बोला, न सोशल मीडिया पर कुछ लिखा।
- फरवरी-2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, तो आप को करारी हार मिली। पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिलीं जबकि बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तब भी राघव चुप्पी साधे रहे। आप के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखे।
- 2025 की शुरुआत में ही राघव के सोशल मीडिया अकाउंट से आप का बैनर और चुनाव निशान हटने लगे। आप के अंदर चर्चा होने लगी कि राघव पार्टी के बजाय पर्सनल ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। वह न पार्टी दफ्तर आते हैं, न किसी नेता से मिलते हैं।
- 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित बाकी आरोपियों को शराब घोटाले में सीबीआई के मामले से बरी कर दिया। आप ने इस का जश्न मनाया, लेकिन राघव नदारद रहे।
- अमेरिका-ईरान जंग छिड़ने के बाद राघव चड्ढा ने पार्टीलाइन पर संसद में बोलने से इनकार कर दिया। हाल में जब पार्टी व्हिप के तहत आप सांसदों ने वॉकआउट किया, तब राघव सदन में ही मौजूद रहे।

पीएम ने हुगली नदी में नाव की सवारी की

नाव चलाने वाले को गले लगाया, 1000 दिए

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हुगली नदी में नाव की सवारी की है। इस दौरान पीएम ने खुद से फोटोग्राफी भी की। तस्वीरों में वे हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने नाविकों से बातचीत भी की। हुगली में नाव की सवारी कराने वाले नाविक को एक हजार रुपए भी दिए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाव की सवारी वाली तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा, ‘हर बंगाली के लिए गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। यह कहना गलत नहीं होगा कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है।’ इससे पहले पीएम 19 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान झाड़ग्राम में रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई।

पीएम मोदी ने हुगली नदी में करीब एक घंटे सैर की।

फास्ट न्यूज

मणिपुर के उखरुल में फायरिंग से 3 की मौत

इंफाल। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार सुबह दो अलग-अलग फायरिंग घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। मुल्लम गांव के पास सुरक्षाबलों ने करीब 11:25 बजे दो शव बरामद किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों आर्मी प्रिंट कपड़ों में थे। उनके शरीर पर गोली के निशान मिले हैं। दूसरी घटना सिनाकेइथेई गांव की है, जहां 29 साल के एच. जमांग नाम के युवक को हमलावरों ने घात लगाकर मार डाला।

चीन गतिरोध में सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा : नरवणे

नई दिल्ली। पूर्व आर्मी चीफ चीफ जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को कहा कि 2020 में चीन के साथ गतिरोध में सरकार ने सेना को अकेला नहीं छोड़ा था। सरकार पूरी तरह से सपोर्ट में थी और पूरा अधिकार दिया था कि हालात बिगड़ने पर चीनी सैनिकों पर गोलियां चला सकें। जनरल नरवणे ने गुरुवार को कुछ चैनल्स को दिए इंटरव्यू में अपनी किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ से जुड़े विवादों पर बात की। इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, ‘जो उचित समझो वह करो’ टिप्पणी सशस्त्र बलों पर सरकार के पूरे भरोसे को दर्शाती है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जमीनी स्थिति का जवाब देने के लिए सशस्त्र बलों को फ्री हैंड दिया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राज्यसभा में नोटिस

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष ने शुक्रवार को राज्यसभा में नोटिस दिया। इस पर 73 सांसदों के दस्तखत हैं। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया।

7 महीने प्रेग्नेंट नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट बोला- यह महिला की इच्छा का सवाल

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सात महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट 15 साल की लड़की को मेडिकल टर्मिनेशन (अबॉर्शन) की इजाजत दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कहा यह जन्म लेने वाले बच्चे का सवाल नहीं है। जरूरी यह है कि लड़की क्या चाहती है। अगर वह बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। भले ही बच्चे को जन्म के बाद गोद देने का ऑप्शन मौजूद हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस स्टेज पर अबॉर्शन करना मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने डिलीवरी के बाद बच्चा गोद देने का सुझाव दिया था। कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लड़की एक

नाबालिग लड़के के साथ आपसी सहमति से संबंध के बाद प्रेग्नेंट हुई थी। नाबालिग की मां ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MPT Act) में तय समयसीमा से आगे जाकर बेटी के अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी। लड़की ने भी कहा था कि वह प्रेग्नेंसी जारी नहीं रखना चाहती। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा गया कि इस प्रेग्नेंसी ने नाबालिग को गंभीर मानसिक तनाव दिया है।

>> (शेष पेज 04 पर)

शाह ने कहा- अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा

टीएमसी का दीया बुझने वाला : मोदी

रैली

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। बुझता दिया फड़फड़ाता है। बंगाल में परिवर्तन की लहर है। पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। पीएम ने महिला आरक्षण पर कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी। महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा।

बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। बंगाल में गुरुवार को पहले फेज में 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान हुआ है। दूसरे फेज में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। लेकिन कुछ दिन पहले संसद में टीएमसी और उसके सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। देश चाहता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं चाहती। आज बंगाल में हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर ‘मातृ शक्ति भरोसा कार्ड’ बांट रहे हैं। हर बहन को हर महीने 3000 रुपए, यानी सालाना 36,000 रुपए की सहायता का आश्वासन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार ने बंगाल की पहचान को खत्म कर दिया है।

>> (शेष पेज 04 पर)

मोदी की स्पीच के 4 पॉइंट्स, कहा-

- बंगाल को टीएमसी से आजादी चाहिए। टीएमसी के डर से आजादी, टीएमसी के भ्रष्टाचार से आजादी, टीएमसी के सिंडिकेट से आजादी, बेटियों पर अत्याचार और बेरोजगारी से आजादी।
- टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, लेकिन पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है।
- जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने की सलाह देती है। टीएमसी नहीं चाहती कि महिलाएं सपने देखें।
- 4 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं पर हुए सभी अत्याचारों की फाइलें खोली जाएंगी। यह मोदी की गारंटी है।

अभिषेक बनर्जी बोले- अपराधी अब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं

पश्चिम बंगाल के जगतबल्लभपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पहले चोर, डकैत, हत्यारे और बलात्कारी अपराध करते थे और जेल जाते थे। अब वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। आप अपने आसपास देखिए, कोई सभ्य या शालीन व्यक्ति बीजेपी का समर्थन नहीं करता। कोई पढ़ा-लिखा या सम्मानित व्यक्ति बीजेपी के साथ नहीं है। सभी चोर, भ्रष्ट लोग, ठग, शराबी, नशेड़ी, गद्दार और बेईमान लोग बीजेपी में हैं।

सुनवाई : एसआईआर लिस्ट से बाहर चुनाव अधिकारियों की याचिका पर कहा- इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे

बंगाल का वोटर टर्नआउट देखकर बहुत खुश हूं : सीजेआई सूर्यकांत

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुई रिकॉर्ड वोटिंग की तारीफ की। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन पंचोली की बेंच ने राज्य में चुनावी हिंसा न होने पर संतोष जताया। CJI ने कहा- भारत के नागरिक के रूप में, मुझे मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुशी हुई। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनके नाम वोटर

लिस्ट से हटा दिए गए हैं, कि वे लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों से संपर्क करें। कोर्ट बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों से कहा कि वे उन लोगों को पहले सुनवाई का मौका दें, जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अर्जेंट सुनवाई की गुहार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को उन विभिन्न लोगों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से काट दिए गए थे; इनमें लगभग 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारी भी शामिल थे।

कोर्ट रूम लाइव

- **एडवोकेट कल्याण बनर्जी:** दायर की गई 27 लाख अपीलों में से 136 का ही निपटारा किया गया है। यह बहुत दुख की बात है। इस बार 92% मतदान हुआ। दूर-दूर से प्रवासी मजदूर मतदान करने आए हैं। हिंसा की कोई घटना भी नहीं हुई।
- **CJI सूर्यकांत:** मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
- **SG तुषार मेहता:** यह ऐतिहासिक मतदान है। लेकिन मैं बनर्जी से सहमत हूं... कुछ घटनाओं को छोड़कर यह एक शांतिपूर्ण चुनाव था।
- **जस्टिस बागची:** राजाये राजाये जुद्धो होये, कुलो कांगरार जान जाए, यानी युद्ध राजाओं के बीच लड़े जाते हैं, लेकिन आम लोग अपनी जान गंवाते हैं। पहली बार चुनाव आयोग के मुवक्किल की सभी लोग सराहना कर रहे हैं।

भारत ने अमेरिका के लिए क्या नहीं किया : राम माधव

टैरिफ झेला, रूस-ईरान से तेल खरीदना बंद किया, बाद में माफी मांगी

विवाद

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। भाजपा नेता और RSS लीडर राम माधव के अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पर बयान को लेकर विवाद हो गया है। माधव ने वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने कहा, 'भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई और अमेरिकी टैरिफ का भी विरोध नहीं किया। हालांकि, विपक्ष की आलोचना के बाद राम माधव ने माफी मांग ली।

“जवाब में राम माधव ने कहा, ‘हमने (भारत ने) ईरान से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति दी। हमने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर भी सहमति दी, जबकि विपक्ष ने काफी आलोचना की। हमने 50% टैरिफ को भी स्वीकार किया। स्वीकार करने का मतलब है कि हमने ज्यादा विरोध नहीं किया।

राम माधव ने कहा था- हमने 18% टैरिफ भी स्वीकार किया

राम माधव वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में एक पैनल चर्चा में शामिल हुए थे। पैनल में पूर्व अमेरिकी राजनयिक एलिजाबेथ श्रेलकेल्ड और अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल भी मौजूद थे। इस दौरान माधव से अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने से जुड़ा सवाल पूछा गया। उन्होंने आगे कहा, अब नए ट्रेड डील में हमने 18% टैरिफ भी स्वीकार किया है, जो पहले से ज्यादा है। तो आखिर भारत कहां पीछे रह रहा है?

सम्पादकीय

नरेन्द्र मोदी पहले हैं या देश?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जब भी फोन पर बात होती है, फौरन उसकी सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन जब ट्रंप भारत के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, भला-बुरा कहते हैं तो सरकार और मीडिया की तरफ से एकदम सन्नाटा छा जाता है। पाठक जानते हैं कि कई मोदी समर्थक पत्रकार तो मोदी-ट्रंप चर्चा पर बिना विस्तृत विवरण जाने ही लहालोट होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इन दोनों नेताओं की दोस्ती साबित करना है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी देश को फौरन इत्तला करते हैं कि मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात हुई। अभी पिछले हफ्ते ही दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट लंबी वार्ता फोन पर हुई। जिसके बारे में बताया गया कि प.एशिया में चल रहे तनाव, होर्मुज बंद होने का असर जैसे मुद्दों पर दोनों ने चर्चा की, आपसी साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। बस इतने में ही मोदी समर्थक गदगद हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को पसंद करता है। लेकिन क्या यही अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को भी पसंद करता है, यह एक बड़ा सवाल है। अक्सर विपक्ष की देशभक्ति की परीक्षा लेने वाले, उनके देशप्रेम को चुनौती देने वाले पत्रकारों और भाजपा के लोगों के लिए भी अब एक परीक्षा का वक्त है कि उनके लिए नरेन्द्र मोदी बड़े हैं या देश बड़ा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक विवादास्पद पोस्ट को दोबारा पोस्ट किया है, जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को 'हेलहोलÓ (नर्क जैसा देश) करार दिया गया है। इस पोस्ट में अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थराइट सिटीजनशिप) की नीति पर तीखा हमला किया गया है। अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने मूल रूप से यह पोस्ट लिखी है। जिससे सहमति जताते हुए ट्रंप रीपोस्ट करते रहते हैं। इस में जन्मसिद्ध नागरिकता का मुद्दा अदालतों के बजाय आम नागरिकों द्वारा तय किए जाने की वकालत की गई है। इसमें अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और अन्य कानूनी संगठनों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये संस्थाएं अवैध आप्रवासन को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रभावित करती हैं, जिससे सार्वजनिक संसाधनों पर बोझ बढ़ता है। पोस्ट में कहा गया है कि जन्मसिद्ध नागरिकता की वजह से अप्रवासी अमेरिका में आसानी से पैर जमाते हैं। इसके अनुसार, 'यहां एक बच्चे का जन्म होते ही वह तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वह अपने पूरे परिवार को चीन, भारत या दुनिया के किसी दूसरे नर्क जैसे देश से यहां बुला लेता है।'

ट्रंप ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता के खिलाफ अपने पुराने रुख को दोहराया है। दूसरा कार्यकाल संभालते ही ट्रंप ने अवैध रूप से रह रहे प्रवासी लोगों को बाहर निकालने का काम किस तरह से किया था, यह भारत ने देखा है। कम से कम तीन बार अमेरिका के सैन्य जहाजों में हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ भारतीयों को वापस भेजा गया था। तब भी विपक्ष ने देश की संप्रभुता की रक्षा का सवाल उठाया था कि अमेरिकी सैन्य विमान हमारी धरती पर कैसे उतरे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं कहा। जब विपक्ष ने भारतीयों के सम्मान का मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि यह उनकी नीति है कि वे अवैध प्रवासियों को बाहर कर रहे हैं। यानी हर तरह से ट्रंप का बचाव करने की कसम मोदी सरकार ने खा ली है। लेकिन फिर देश का बचाव कौन करेगा, यह सवाल अब और गंभीरता से उठ रहा है। क्योंकि इस बार भारत को सीधे नर्क जैसी जगह कहा गया है। ट्रंप ने अगर ऐसी कोई पोस्ट मोदी की तारीफ में लिखी होती तो अब तक उस पर ढिंढोरा पीटा जा चुका होता, लेकिन देश को नर्क कहा जा रहा है और मोदी सरकार ने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक एक शब्द भी विरोधस्वरूप दर्ज नहीं कराया है। वैसे तो खुद नरेन्द्र मोदी भी कह चुके हैं कि 2014 से पहले भारतीय सोचते थे कि पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा पाप किया है, जो इस देश में जन्म लिया। यह भी देशविरोधी वक्तव्य था। लेकिन प्रधानमंत्री ने दिया था तो आलोचना की गई। इस बार मामला दूसरा है। इस बार देश के प्रधानमंत्री ने नहीं, दूसरे देश के राष्ट्रपति ने हमारे देश को नर्क बताया है तो उस पर चुप्पी साधना कायरता ही कहलाएगी। छोटे से छोटा देश भी इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन भारत सरकार यानी मोदी सरकार क्यों चुप है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने तो इस घटनाक्रम पर भड़कते हुए, अपनी तत्काल प्रतिक्रिया में कहा है कि ये बात बेहद अपमानजनक है और भारतविरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि, जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक-रिकॉर्ड रहा है।

> *"वाक्यांश दुश्मन के साथ सोना किसी विरोधी के साथ घनिष्ट संबंध या सहयोग को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ अक्सर विश्वासघात का जोखिम होता है। इस संदर्भ में, यह मेघाता के बारे में चिंताओं को रेखांकित करता है, खासकर जब किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास बढ़ाया जाता है जिसके करीबी सहयोगी के राज्य के विरोधी हित हो सकते हैं।*

हाल ही में, मणिपुर में वाई. खेमचंद सिंह की सरकार के गठन के बाद हिंसा में नए सिरे से वृद्धि देखी जा रही गई

हाल ही में, मणिपुर में वाई. खेमचंद सिंह की सरकार के गठन के बाद हिंसा में नए सिरे से वृद्धि देखी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृद्धि कुकी समुदाय से एक उपमुख्यमंत्री को शामिल करने के साथ मेल खाती है, जिसकी पत्नी कथित तौर पर एक विद्रोही संगठन की प्रमुख है। संगठन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गृह मंत्रालय के साथ संचालन निलंबन (एसओओ) समझौते को सितंबर 2025 से बढ़ा दिया है। हालाँकि, इसका मतलब स्थायित्व नहीं है। संशोधित जमीनी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा एसओओ समझौते को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। आमतौर पर सालाना नवीनीकृत किया जाता है, इसकी निरंतरता इन नियमों के पालन पर सख्ती से निर्भर करती है और इसे दीर्घकालिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता है। यह महत्वपूर्ण सवाल उठाता है: क्या एक विद्रोही नेता के जीवनसाथी के लिए नैतिक रूप से स्वीकार्य और प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण है, यहां तक कि वर्तमान में युद्धविराम या एसओओ समझौते के तहत भी, मंत्रिपरिषद में सेवा करना नैतिक रूप से स्वीकार्य और प्रशासनिक रूप से विवेकपूर्ण है? ऐसे विद्रोही समूह ऐतिहासिक रूप से राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं और यदि राजनीतिक वार्ता विफल हो जाती है या केंद्र समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला करता है तो उन्हें फिर से शुरू कर सकते हैं। क्या ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को राज्य के रहस्य सौंपे जाने चाहिए और संवेदनशील सुरक्षा नीति निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए? क्या इस तरह के व्यक्तिगत संबंध वाले मंत्री की उपस्थिति राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का जोखिम उठाती है? क्या कैबिनेट के सदस्य, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं? इन चिंताओं को इस व्यवस्था के नैतिक, कानूनी और संवैधानिक आयामों के बारे में जनता के संदेह और धारणाओं को दूर करने

के लिए मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 19 अप्रैल 2026 को, मणिपुर के गृह मंत्री, गोविंददास कोंथौजम ने घोषणा की कि पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों में एसओओ समझौते के तहत आतंकवादी संगठनों के सभी अनधिकृत शिविरों को एक महीने के भीतर बंद कर दिया जाएगा। एसओओ समूहों और शांति निगरानी समिति के परामर्श से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य स्थिरता बहाल करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी कैडरों को निर्दिष्ट शिविरों के भीतर रहना चाहिए और संशोधित जमीनी नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालाँकि, ये बयान अनधिकृत शिविरों के अस्तित्व और प्रवर्तन में चूक का संकेत देते हैं। उनका यह भी संकेत है कि गृह मंत्रालय की अध्यक्षता वाले संयुक्त निगरानी समूह के निर्देशों को अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है। इन आश्वासनों के बावजूद, सार्वजनिक चिंताएं बनी हुई हैं, खासकर हाल ही में हिंसा में वृद्धि के आलोक में। सवाल उठते हैं कि सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील सुरक्षा जानकारी लीक न हो। एसओओ उल्लंघनों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई पर कैबिनेट चर्चा कैसे आयोजित की जाएगी? वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपमुख्यमंत्री के साथ आयोजित कैबिनेट की बैठकें कितनी सुरक्षित हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति कमरे में मौजूद न हो या कैबिनेट की बातचीत न सुन सके? इस तरह के उल्लंघनों की स्थिति में किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? यदि उपमुख्यमंत्री को इस तरह की चर्चाओं से बाहर रखा जाता है, तो यह विचार-विमर्श की प्रकृति का संकेत दे सकता है। यदि इसमें शामिल किया जाता है, तो हितों के टकराव के बारे में चिंताएं अनसुलझी रहती हैं। यह एक जटिल शासन दुविधा पैदा करता है। इंफाल-उखरुल रोड पर टीएम कासोम गांव में नागरिक वाहनों पर कुकी उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किया गया हमला, जिससे लितान में सशस्त्र एस्कॉर्ट सेवा के रुकने के बाद दो तांगखुल नागरिकों की मौत हो गई, जिससे संवेदनशील सुरक्षा संबंधी घटनाओं की अखंडता पर संदेह पैदा हो गया है। इसी तरह, बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलोबी गांव में बम हमले में दो बच्चों की दुखद मौत ने सार्वजनिक चिंता और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। क्या राज्य सरकार इन पहलुओं की सक्रिय रूप से जांच करेगी, या सुधारात्मक कार्रवाई करने से पहले और गंभीर घटनाओं की प्रतीक्षा करेगी? क्या राज्य के सुरक्षा ढांचे के भीतर संभावित कमजोरियों को जोखिम में डालना समझदारी है? ये गंभीर चिंताएँ हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान को इन मुद्दों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आबादी के कुछ हिस्से, विशेष रूप से नागा और मैतेई समुदायों के बीच, वर्तमान व्यवस्था से तेजी से असुरक्षित महसूस कर हैं। इसका मतलब यह है कि कुकी उस क्षेत्र में मौजूद नहीं हैं जहां मैतेई सैनिक के घर पर हमला किया गया था। राज्य में विभाजन इतना व्यापक है कि मेइतेई कुकी बहुसंख्यक तक नहीं पहुंच सकते हैं और कुकी मैतेई क्षेत्र से बहुत दूर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सामाजिक दंगों का इतिहास बताता है कि जिस क्षेत्र में वह अल्पसंख्यक है, वहां कोई भी समुदाय बहुसंख्यक नहीं होता है, लेकिन यह सामान्य ज्ञान है। चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, जो लोग जानते हैं कि उन पर हमला करने वाला कोई नहीं होगा, वे ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए, मैतेई द्वारा पीटे जाने के बाद, जब यह देखा जाता है कि प्रशासन मैतेई समर्थक है। मैं, कुकी स्वयं अपने क्षेत्रों में जाते हैं और पाते हैं कि वे मैतेई समर्थक हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो भी क्षेत्र के नेता का पहला कर्तव्य यह देखना चाहिए कि धार्मिक वैमनस्य फिर से पैदा न हो। बीरेन सिंह ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, न ही वह इसे अपनी जगह पर आए अन्य शेरों को देना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि उनमें शांति पैदा करने की क्षमता न हो। किसी भी मामले में, तो केंद्र को यह करना चाहिए। यह विश्वास करना मुश्किल है कि भारतीय नेतृत्व अपने ही पिछवाड़े में इस आग को नहीं बुझा सकता है, जब वास्तविक दुनिया के संघर्षों और गृहयुद्धों में शांति के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका का सार्वभौमिक अहसास हो रहा है। मणिपुर कभी एक राजशाही थी, जिसे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया था।

■ सुभाष शिरढोनकर

अगर तमिलनाडु एक...

टी एन अशोक

भारत के क्षेत्रीय दिग्गज कर रहे 'उत्तर के शासकों' की घेराबंदी का सामना

> *गणित का हिसाब-किताब बहुत ही कड़ा है। भाजपा सौ का आंकड़ा पार करने के लिए ज़ोरदार कोशिश कर रही है-ताकि उसकी सीटों की संख्या तीन अंकों (90-110) तक पहुंच जाए। टीएमसी के लिए चुनौती अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की है। 155 सीटें भी रह जाना-ममता बनर्जी को साधारण बहुमत तो दिला ही देगी।*

हम यहां भारतीय संघ के बारे में दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोणों के टकराव को देख रहे हैं। एक तरफ, क्षेत्रीय सत्ताधारी दल 'बहुलवादी प्रतिरोध' का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां राज्य की पहचान ही राजनीति का मुख्य आधार होती है। दूसरी तरफ, भाजपा 'केंद्रीकृत एकीकरण' का प्रतिनिधित्व करती है, जो इन क्षेत्रीय गढ़ों को शासन के एक ही, राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लागू करने में अंतिम बाधाओं के रूप में देखती है। भारत का चुनावी नक्शा कोई एक जैसी चीज़ नहीं है। यह अलग-अलग, और अक्सर अपनी बात पर अड़े रहने वाले राजनीतिक अंदाज़ों का एक संग्रह है। जैसे-जैसे तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल एक बड़ी दांव वाली, दो चरणों वाली लंबी चुनावी दौड़ के अन्तिम चरण की ओर बढ़ रहा है, उनके पीछे का संदेश एक ही है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। संदेश है कि वे पारंपरिक क्षेत्रीय गढ़, जो लंबे समय से भारतीय संघवाद की मज़बूत दीवारें बने हुए थे, अब धीरे-धीरे और सोची-समझी रणनीति के तहत जोरदार घेराबंदी का सामना कर रहे हैं। दशकों तक, भारतीय लोकतंत्र की कहानी राज्यों की भाषाओं में लिखी जाती रही। चेन्नई में, यह 'द्रविड़ मॉडल' था, जिसकी पहचान करिश्मा और अस्मिता से होती थी। कोलकाता में, यह 'कैडर मशीन' थी, जिसकी पहचान वैचारिक वर्चस्व से होती

थी। लेकिन 2026 की गर्मियों में, ये क्षेत्रीय किले यह महसूस कर रहे हैं कि आरामदेह और बिना किसी चुनौती वाले वर्चस्व का दौर अब खत्म होने वाला है। इसकी जगह अब एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक मशीन के दखल के खिलाफ़ एक सीधी और ज़ोरदार लड़ाई ने ले ली है। चेन्नई के उमस भरे और हलचल भरे गलियारों में, एम. के. स्टालिन न सिफ़र् अपने विरोधियों से, बल्कि अतीत के साये से भी लड़ रहे हैं। 'भगवान-राजा' का दौर—यानी एम. जी. रामचंद्रन या जयललिता जैसे फ़िल्मी अंदाज़ वाले, आम इंसान से कहीं बढ़कर माने जाने वाले मसीहाओं का दौर—अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया है जिसे कोई भी भाषणबाज़ी नहीं भर सकती। स्टालिन ने राजनीतिक शायरी की जगह प्रशासनिक गद्य को अपनाने की कोशिश की है। उनकी सरकार गठबंधन बनाने की एक बहुत ही सधी हुई और पेंचीदा बुनावट वाली है: जिसमें किसानों के संगठनों, अलग-अलग समुदायों और वामपंथी झुकाव वाले छोटे-छोटे गुटों के अलग-अलग हितों को एक साथ पिरोया गया है। यह एक ज़बरदस्त और आधुनिक रणनीति है, लेकिन यह नाज़ुक भी है। भाजपा, जो अन्नाद्रमुक के कंधे पर सवार है, ने इस नाज़ुकता को पहचान लिया है। वे सीधे-सीधे जीत हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं—जो कि द्रविड़ धरती पर किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए अभी भी पहुंच से बाहर की बात है—लेकिन वे बड़ी होशियारी से द्रमुक के जीत के अंतर को कमज़ोर कर रहे हैं। अनुमानों से पता चलता है कि द्रमुक, जिसके पास 2021 में 133 सीटें थीं, फिसल कर बहुत कम यानी 115-120 सीटों पर आ सकती है। स्टालिन की शासन शैली, जो नई दिल्ली के खिलाफ 'टकराव वाले संघवाद' पर आधारित है, उनके शासन को राष्ट्रीय वर्चस्व का एकमात्र विकल्प बनाने का एक सोचा-समझा प्रयास है। लेकिन अगर सीटें कम होती हैं, तो द्रमुक का स्थिर बहुमत एक 'त्रिशंकु विधानसभा' की उथल-पुथल में बदल सकता है। यदि ऐसा होता है तो इससे यह साबित हो जाएगा कि एक सुव्यवस्थित गठबंधन भी उस राष्ट्रीय पार्टी के लगातार दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता, जो हर एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, इंच-दर-इंच लड़ने को तैयार हो। अगर तमिलनाडु एक शतरंज का खेल है, तो पश्चिम बंगाल एक सड़क की लड़ाई है।

इस सीरीज में...

सुभाष शिरढोनकर

कियारा आडवाणी का कन्नड़ फिल्मों में डेब्यू

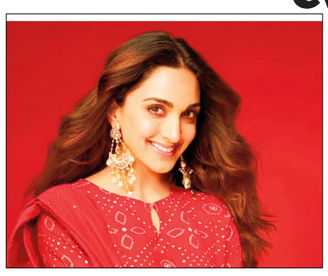

निर्देशक गीतु मोहनदास व्दारा निर्देशित फिल्म 'टॉक्सिकः ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन -अप्स' अपनी घोषणा के बाद से लगातार चर्चाओं में है। फिल्म में यश के नए लुक के साथ-साथ नादिया का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी खासी सुर्खियों में है। कियारा आडवाणी की इस फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित है। कन्नड़ के अलावा इंग्लिश भाषा में भी बन रही इस फिल्म के साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी कन्नड़ में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म के लिए उन्हें 15 करोड़ की तगड़ी फीस मिली है। 'टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन -अप्स' पहले 19 मार्च को 'धुरंधरः द रिवेंज' के साथ ही रिलीज होने वाली थी लेकिन आदित्य धर के इस फिल्म के प्रति ऑडियंस के जबर्दस्त क्रेज को देखते हुए फिल्म की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया। अब यह 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 'टॉक्सिकः ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन -अप्स' एक जबरदस्त एक्शन फिल्म होने वाली है। फिल्म में यश का डबल रोल है। उनके साथ कियारा आडवाणी के साथ हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। कियारा आडवाणी का नाम आज बॉलीवुड की उन टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने महज एक दशक के करियर में अनेक हिट फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। कबीर सदानन्द की फिल्म 'फगली' (2014) के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली कियारा आडवाणी को फिल्म 'एमएस धोनीःएन अनटोल्ड स्टोरी' (2016) में महेन्द्र सिह धोनी की बीवी, साक्षी के छोटे किरदार के जरिए बॉलीवुड में खास पहचान मिली। उसके बाद 'लस्ट स्टोरीज

(2018) के सनसनीखेज किरदार में कियारा ने हंगामा ही मचा दिया। इस सीरीज में उनके वाइब्रेशन वाले सीन की खूब चर्चा हुई। कियारा आडवाणी ने हिंदी के साथ साउथ की भी कुछ फिल्में की हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों में जिस रेंज में अपने टेलेंट का प्रदर्शन किया है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि वह सिर्फ एक ग्लैमर डॉल ही नहीं, बल्कि उससे बढकर कहीं अच्छी एक्ट्रेस हैं। अपने फैशन सेंस और लुक से फैंस को इम्प्रेस करने वाली कियारा आडवाणी आज के दौर में बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं। फैंस को हर वक्त उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछली बार कियारा आडवाणी, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म 'वॉर 2' (2025) में खुफिया एजेंसी के एजेंट के किरदार में नजर आई थीं लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। पिछले साल ही कियारा आडवाणी तेलुगु रिलीज 'गेम चेंजर' (2025) में रामचरण के अपोजिट नजर आई थी लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं से मुकाबला करते हुए एक आईएएस अधिकारी की कहानी पर बेस्ड एस शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गच्चा खा गई थी।

जरा हटके

यदि इसे सही ढंग...

आशिया खातून

फैमिली आईडी-एक परिवार, एक पहचान, योजनाः पारदर्शी और समावेशी शासन की दिशा में एक सशक्त पहल

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, एक बड़ी चुनौती रही है। कई बार योजनाओं की उचित जानकारी, प्रक्रिया की जटिलता और पहचान संबंधी समस्याओं के कारण वास्तविक लाभार्थी इनसे वंचित रह जाते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "फैमिली आईडी एक परिवार, एक पहचान योजना" की शुरुआत की गई है। यह योजना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सु.ढ़ बनाती है, बल्कि प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करके उन्हें सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने का कार्य भी करती है। फैमिली आईडी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध क्रियान्वयन और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के उन तक पहुंच सके। यह योजना सरकारी सेवाओं को सरल और सुलभ बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जब किसी परिवार की समस्त जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, तो नागरिकों को बार-बार अलग-अलग विभागों में जाकर दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया तेज, सुगम और अधिक प्रभावी बनती है। फैमिली आईडी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। इस पहचान संख्या के माध्यम से परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी जैसे आय, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति आदि एक ही डेटाबेस में संग्रहीत की जाती है। जिन परिवारों के पास पहले से राशन कार्ड उपलब्ध है, उनके लिए राशन कार्ड संख्या को ही फैमिली आईडी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वहीं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए अलग से फैमिली आईडी बनाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए एक

ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जहां परिवार स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं। प्रदेश में राशन कार्ड धारकों की संख्या लगभग 3.64 करोड़ परिवारों की है, जिनमें करीब 14.60 करोड़ लोग शामिल हैं। इन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 मार्च 2026 तक लगभग 44,32,090 परिवारों की फैमिली आईडी बनाई जा चुकी है, जो इस योजना की सफलता और तेजी से हो रहे विस्तार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश और केंद्र सरकार के 32 विभागों की 98 योजनाओं एवं सेवाओं को फैमिली आईडी डेटाबेस के साथ जोड़ा जा चुका है। राज्य के राशन कार्ड धारक परिवारों (3.64 करोड़ परिवार एवं 14.60 करोड़ व्यक्ति) कि राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई डी है। ऐसे परिवार जिनके राशन कार्ड नहीं है, कि फैमिली आईडी बनाये जाने के लिए पोर्टल फैमिली आईडी एक परिवार, एक पहचान योजना के अनेक लाभ हैं, जो इसे एक अत्यंत प्रभावी और नागरिक-केंद्रित पहल बनाते हैं। ये लाभ न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को सु.ढ़ करते हैं, बल्कि आम जनता के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक हैं। इस योजना के तहत सभी डेटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहता है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आती है। इससे भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों की संभावना कम होती है तथा प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है। फैमिली आईडी के माध्यम से प्रदेश सरकार को यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो रही है कि कौन सा परिवार किस योजना के लिए पात्र है। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।

योजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और उनकी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वे एक ही स्थान से अनेक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पहले नागरिकों को हर योजना के लिए अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। फैमिली आईडी के माध्यम से यह प्रक्रिया सरल हो गई है और नागरिकों को बार-बार दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

यह योजना डिजिटल माध्यमों के उपयोग को बढ़ावा देती है, इससे न केवल नागरिकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ रही है। बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के "डिजिटल इंडिया" के लक्ष्य को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फैमिली आईडी के माध्यम से सरकार प्रत्येक परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकती है। इससे जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जा सकती है, जिससे सामाजिक सुरक्षा तंत्र मजबूत होता है। इस योजना के अंतर्गत एकत्रित डेटा सरकार को सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। इससे सरकार को बेहतर नीतियां बनाने और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक है। फैमिली आईडी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इससे योजनाओं की पहुंच बढ़ती है और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाते हैं।

यह योजना व्यक्ति के बजाय परिवार को एक इकाई के रूप में पहचान प्रदान करती है। इससे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ योजनाओं का लाभ मिल सकता है और उनकी समग्र उन्नति सुनिश्चित होती है। फैमिली आईडी के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आई है। अधिकारियों को लाभार्थियों की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो जाती है। डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी प्रणाली के कारण फर्जी लाभार्थियों और बिचौलियों की भूमिका कम हो रही है। इससे योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। जिससे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। फैमिली आईडी योजना भविष्य में एक व्यापक पहचान प्रणाली का आधार बन सकती है, जिससे देशभर में एक समान पहचान प्रणाली विकसित की जा सके। फैमिली आईडी योजना "डिजिटल इंडिया" और "सुशासन" के सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बांग्लादेश बोर्ड ने एनओसी देने से मना किया, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद नहीं लौटेंगे पाकिस्तान

मुस्तफिजुर और नाहिद पीएसएल 2026 के बचे हुए मैच नहीं खेलेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

बांग्लादेश क्रिकेट में एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां Bangladesh Cricket Board (BCB) ने अपने दो प्रमुख तेज गेंदबाजों Mustafizur Rahman और Nahid Rana को लेकर अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) वापस ले लिया है, जिसके चलते अब ये खिलाड़ी Pakistan Super League 2026 के शेष मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान जहां Lahore Qalandars का हिस्सा थे, वहीं नाहिद राणा Peshawar Zalmi की टीम से जुड़े हुए थे। दोनों खिलाड़ी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश लौटे थे, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा। दूसरी ओर, नाहिद राणा को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम दिया गया है। लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से बोर्ड ने उनके ऊपर दबाव कम करने का फैसला लिया है। यही वजह है कि उन्हें भी PSL में दोबारा शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, BCB ने आगामी टी-20 सीरीज को ध्यान में रखते हुए मुस्तफिजुर रहमान और Taskin Ahmed को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो टी-20 मैचों से बाहर रखा है।

अब इन खिलाड़ियों के आगामी कार्यक्रम पर भी नजर टिकी हुई है। नाहिद राणा मई में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी कर सकते हैं। वहीं मुस्तफिजुर रहमान के जून में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वाइट बॉल सीरीज (वनडे और टी-20) में खेलने की संभावना जताई जा रही है।

चोट और फिटनेस बनी बड़ी वजह

BCB ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि मुस्तफिजुर रहमान इस समय घुटने की चोट से जूझ रहे हैं। उनकी स्थिति का सही आकलन करने के लिए जल्द ही मेडिकल स्कैन कराया जाएगा। इसके बाद वे बोर्ड की मेडिकल टीम की निगरानी में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से गुजरेंगे। गौरतलब है कि इसी चोट के कारण मुस्तफिजुर न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती दो वनडे मैचों में नहीं खेल सके थे। हालांकि तीसरे मुकाबले में उन्होंने शानदार वापसी करते हुए 5 विकेट झटककर अपनी उपयोगिता साबित की थी।

क्या होता है एनओसी?

क्रिकेट में NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जब कोई खिलाड़ी अपने देश के बाहर किसी विदेशी लीग—जैसे PSL या IPL—में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसे अपने राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से इसकी अनुमति लेनी होती है। यह अनुमति खिलाड़ी की फिटनेस, इंटरनेशनल शेड्यूल और वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। बोर्ड के पास यह अधिकार होता है कि वह किसी भी समय NOC को रद्द कर दे, जैसा कि इस मामले में देखा गया है।

गायकवाड ने मुंबई के खिलाफ जीत मुकेश को समर्पित की

मां के निधन के बावजूद मैदान पर उतरे थे गेंदबाज, टीम ने भी काली पट्टी बांधी

नई दिल्ली, एजेंसी

वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की 103 रनों की शानदार जीत एक भावुक मोड़ पर खत्म हुई। जीत के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने इस प्रदर्शन को अपने साथी खिलाड़ी मुकेश चौधरी को समर्पित किया। मुकेश हाल ही में अपनी मां को खोने के बावजूद टीम के लिए खेलने मैदान पर उतरे थे। मुकेश चौधरी के प्रति सम्मान और एकजुटता दिखाने के लिए चेन्नई के सभी खिलाड़ियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी थी। पारिवारिक दुख के बीच मुकेश ने न केवल वापसी की, बल्कि मैदान पर शानदार जज्बा भी दिखाया। उन्होंने अपने स्पैल (1/31) के दौरान मुंबई के ओपनर क्विंटन डी कॉक को जल्दी आउट कर मैच की दिशा तय कर दी। मैच के बाद गायकवाड काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मुकेश जानते थे कि टीम को उनकी जरूरत है, इसलिए वे फ्रेंचाइजी और टीम के लिए वापस आए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने संजू सैमसन की नाबाद 101 रनों की पारी की बदौलत 207/6 का स्कोर खड़ा किया। गायकवाड ने संजू की तारीफ करते हुए कहा, संजू ने शानदार पारी खेली, वे बेहतरीन फॉर्म में हैं। टॉस के वक्त मैं थोड़ा दुविधा में था, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि पिच सूखी होने के साथ थोड़ी हरी भी थी। हमें लगा था कि 200 का स्कोर अच्छा रहेगा। 208 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम महज 104 रन पर सिमट गई। चेन्नई की ओर से अकील हुसैन और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। गायकवाड ने गेंदबाजों पर संतोष जताते हुए कहा कि हमारी बॉलिंग में पिछले मैचों के मुकाबले सुधार हो रहा है और अब टीम सही लय में आ रही है।

फास्ट न्यूज

फिल्म हक के लिए यामी गौतम ने कुरान पढ़ी थी

मुंबई। फिल्म हक की एक्ट्रेस यामी गौतम ने अपने किरदार की तैयारी और फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए करीब चार महीनों तक कुरान पढ़ी थी। यह बात फिल्म के डायरेक्टर सुपर्न वर्मा ने बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में बताई। सुपर्न वर्मा ने बताया कि फिल्म की रिसर्च के दौरान इस्लामी कानून समझने में टीम को करीब डेढ़ साल लगा था।

सिंगर रिहाना दूसरी बार भारत पहुंचीं

नई दिल्ली। इंटरनेशनल सिंगर रिहाना शुक्रवार को दूसरी बार भारत पहुंचीं। मुंबई के कलिना एयरपोर्ट पर उनका फैंस और पैपराजी ने स्वागत किया। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, मुस्कुराईं और कार में बैठने से पहले फ्लाइंग किस जेस्चर किया। इससे पहले सिंगर साल 2024 में भारत आई थीं। बताया जा रहा है कि वह मुंबई में एक ब्यूटी ब्रांड से जुड़े एक इवेंट में शामिल होने भारत पहुंची हैं। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। रिहाना प्राइवेट जेट से मुंबई पहुंचीं। उन्होंने ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था और पोनीटेल, डार्क सनग्लासेस और गोल्ड ज्वेलरी के साथ अपने लुक को पूरा किया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय पैपराजी उन्हें 'रीरी' कहकर बुलाते सुनाई दिए। रिहाना ने जवाब में हाथ हिलाया और मुस्कुराईं।

इंफोसिस का मुनाफा चौथी तिमाही में 21% बढ़ा

मुंबई। आईटी कंपनी इंफोसिस ने 23 अप्रैल को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर 8,501 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में 7,033 करोड़ का मुनाफा हुआ था। ऑपरेशन्स से होने वाला रेवेन्यू करीब 13.38% बढ़ा। यह 46,402 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 40,925 करोड़ था। वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से मिलने वाला पैसा रेवेन्यू होता है।

'मैं काफी अनकम्फर्टेबल थी'

काजोल ने डेब्यू वेब सीरीज के लिए 30 साल बाद नो-किस पॉलिसी तोड़ी थी

वेब सीरीज में जीशु सेनगुप्ता ने राजीव सेनगुप्ता के किरदार में काजोल के पति की भूमिका निभाई थी।

मुंबई, एजेंसी

एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में बताया कि वेब सीरीज 'द ट्रायलः प्यार, कानून, धोखा' में पहला ऑनस्क्रीन किस करने को लेकर शुरुआत में वह असहज थीं। उन्होंने बताया कि तीन दशक पुरानी नो किसिंग पॉलिसी उन्होंने सिर्फ किरदार की डिमांड के कारण तोड़ी थी। काजोल ने अपने तीन दशक लंबे करियर में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'कुछ कुछ होता है' और 'कभी खुशी कभी गम' जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। प्यार, कानून, धोखा' से ओटीटी डेब्यू करते हुए उन्होंने पहली बार ऑनस्क्रीन को-स्टार जिस्सू सेनगुप्ता के साथ किस सीन दिया था।

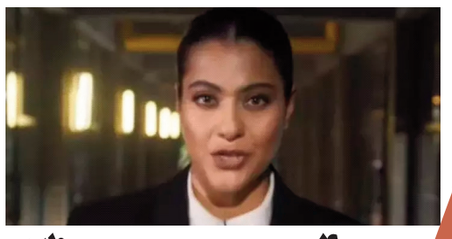

'मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी'-काजोल

जब पॉडकास्ट में पूछा कि क्या एक इंसान के तौर पर भी काजोल बदलीं, जिससे उन्हें यह करने में सहज महसूस हुआ, तो एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं इससे अनकम्फर्टेबल थी। सेट पर जाने तक मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी। बाद में सोचने पर यह ठीक लगा, लेकिन मुझे पक्का नहीं था कि मैं सच में यह करूंगी या बीच में बोल दूंगी, 'कट! यह नहीं होगा!' लेकिन मुझे लगा कि यह एक प्रोफेशनल फैसला था और उस दिन मैं यह फैसला ले सकती थी।'

लिली सिंह के पॉडकास्ट में काजोल से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो यह उस रोल की जरूरत थी, जो मैं निभा रही थी। इसका बहुत संबंध उस रोल और उसकी सोच से था। यह सिर्फ एक किस नहीं था। यह इस बारे में था कि वह क्या सोचती थी, क्या चाहती थी और उसके साथ क्या नहीं हुआ। वह किस बात पर भरोसा करती थी, किस बात पर विश्वास रखती थी और किस बात पर नहीं रख सकती थी। यह पूरी कहानी का बहुत जरूरी हिस्सा था, इसलिए इसे हटाना मतलब किरदार के एक अहम हिस्से को हटाना होता।'

सलमान खान की नई फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होगी

'एसवीसी63' के मुहूर्त की झलक शेयर की, वीडियो में दिखीं नयनतारा

मुंबई, एजेंसी

सलमान खान ने शुक्रवार को अपनी आने वाली फिल्म 'SVC63' के मुहूर्त की कुछ झलकियां शेयर कीं। साथ ही बताया कि फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होगी। इस फिल्म का डायरेक्शन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं। सलमान ने इंस्टाग्राम पर एक रील वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह और नयनतारा दिख रहे हैं। वीडियो में एक क्लैपबोर्ड दिखाया गया है, जिस पर मुहूर्त लिखा है। सलमान ने कैप्शन में लिखा कि थोड़ा दूर की सोच रखनी चाहिए, इसलिए ईद 2027 की घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी फिल्म की जानकारी भी सही समय पर दी जाएगी और फैंस से धैर्य रखने को कहा। इस फिल्म से सलमान पहली बार डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ काम करे रहे हैं। इस फिल्म को अस्थायी नाम SVC63 दिया गया है। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली बड़े स्केल पर फिल्में बनाने के साथ-साथ उनमें मजबूत इमोशनल कहानी पिरोने के लिए जाने जाते हैं। वामशी इससे पहले प्रभास (मुन्ना), जूनियर एनटीआर (बृंदावनम), महेश बाबू (महर्षि), राम चरण (येवडु) और विजय (वारिसु) जैसे सितारों के साथ काम कर चुके हैं। वहीं, फिल्म को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं।

- नयनतारा भी ब्लैक आउटफिट और ब्लैक सनग्लासेस में एलिगेंट लुक में दिखीं।
- सलमान ने वामशी पेडिपल्ली से गले मिले और दिल राजू से भी मुलाकात की।

पैर काटने की नौबत, नकली पैर लगेगा, अब ईरान को सेना के जनरल चला रहे

मुजतबा खामेनेई का चेहरा-होंठ जला, प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत

तेहरान, एजेंसी

28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मुजतबा खामेनेई के पिता (अयातुल्ला अली खामेनेई) के ठिकाने पर हमला किया था, तब से वह छिपकर रह रहे हैं। उसी हमले में अयातुल्ला खामेनेई, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। मुजतबा खुद भी घायल हो गए और अब डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखभाल कर रही है। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान जो पेशे से हार्ट सर्जन हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके इलाज में शामिल रहे हैं। मुजबता से मिलने बड़े अधिकारी और सेना के कमांडर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें डर है कि इजराइल उनके जरिए ठिकाने का पता लगाकर हमला कर सकता है। यह पूरी जानकारी कई वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व अधिकारियों, सेना के लोगों और जानकारों से बातचीत के आधार पर सामने आई है।

मुजतबा खामेनेई की हालत गंभीर रही है, लेकिन दिमाग से वह पूरी तरह एक्टिव हैं। उनके एक पैर का तीन बार ऑपरेशन हुआ है और अब उन्हें नकली पैर लगाना पड़ेगा। एक हाथ की भी सर्जरी हुई है और वह धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। उनके चेहरे और होंठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे बोलना मुश्किल है और आगे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी।

जंग शुरू होने के बाद से गायब हैं मुजतबा

कागज पर लिखे संदेश लिफाफे में बंद करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, जो कार या बाइक से उनके छिपे ठिकाने तक जाते हैं। उनके जवाब भी इसी तरह वापस आते हैं। उनकी सुरक्षा, चोटें और उनसे संपर्क की कठिनाई की वजह से फिलहाल फैसले लेने की जिम्मेदारी सेना के जनरलों को दे दी गई है। हालांकि देश में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन असली ताकत अब सेना के पास है। मुजतबा का सेना से पुराना रिश्ता भी है।

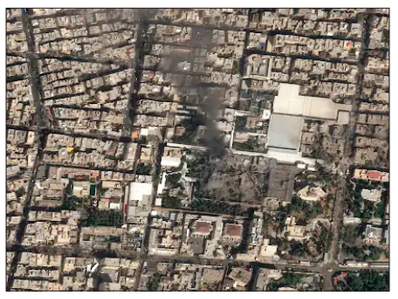

कंपनी डायरेक्टर की तरह देश चला रहे मुजतबा

जब अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे, तब युद्ध, शांति और अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े फैसले वही अकेले लेते थे। उनके पास पूरी ताकत थी। लेकिन उनके बेटे और अब के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई का वैसा रोल नहीं है। मुजतबा खामेनेई एक ऐसे नेता हैं, जो सामने नहीं आते। मार्च में पद संभालने के बाद से उन्हें किसी ने देखा नहीं और उनकी आवाज भी सार्वजनिक रूप से नहीं सुनी गई। उनकी जगह अब ईरान की सेना, खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के बड़े कमांडर और उनसे जुड़े लोग, देश के अहम फैसले ले रहे हैं। सुरक्षा, युद्ध और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर वही सबसे ज्यादा असर रखते हैं।

मुजतबा ने अब तक कोई वीडियो या ऑडियो मैसेज नहीं दिया, क्योंकि वह कमजोर नहीं दिखना चाहते। उनकी तरफ से सिर्फ लिखित बयान जारी किए जाते हैं, जो ऑनलाइन डाले जाते हैं या टीवी पर पढ़े जाते हैं।

सेंसेक्स 1200 अंक गिरकर 76,400 पर कारोबार कर रहा

निफ्टी में 300 अंकों की गिरावट, आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली

मुंबई, एजेंसी

सेंसेक्स 24 अप्रैल को 1200 अंक (1.58%) की गिरावट के साथ 76,400 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 300 अंकों (1.06%) की गिरावट है, ये 23,850 के स्तर पर आ गया है। आज के कारोबार में मीडिया और आईटी के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सीजफायर की 22 अप्रैल की डेडलाइन को आगे तो बढ़ा दिया है, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी अब भी जारी रखी है, वहीं ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में दो जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों देशों के बीच बातचीत का पिछला दौर किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होगी। हालांकि, अब निवेशकों को ऐसी किसी भी बातचीत की उम्मीद नहीं है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इस्लामाबाद यात्रा भी टल गई है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद इंफोसिस के शेयर में आज 6% से ज्यादा की गिरावट है। ये 1,150 रुपए पर कारोबार कर रहा है। ये शेयर का 5 साल का निचला स्तर है। हालांकि, कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% बढ़कर 8,501 करोड़ रहा। पिछले साल इसी तिमाही में 7,033 करोड़ का मुनाफा हुआ था। ऑपरेशन्स से होने वाला रेवेन्यू करीब 13.38% बढ़ा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। बाजार में तेल की मजबूत डिमांड और 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' को लेकर चिंता बढ़ी है जिस वजह से ये तेजी आई है।

बैठक : वित्त मंत्री सीतारमण ने हाई-लेवल मीटिंग की, क्या है मिथॉस और यह क्यों खतरनाक

मिथॉस एआई से बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बैंकों के प्रमुखों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस बैठक में एंथ्रोपिक के 'क्लॉड मिथॉस' AI मॉडल से बैंकिंग सेक्टर को होने वाले संभावित खतरों पर चर्चा की गई। यह एआई मॉडल इतना एडवांस है कि हैकर इसका इस्तेमाल दशकों पुरानी अज्ञात खामियों को खोजकर फाइनेंशियल सेक्टर पर साइबर हमले कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों को अपने IT सिस्टम को सुरक्षित करने और कस्टमर डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मिथॉस से पैदा होने वाला खतरा ऐसा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल और हाई लेवल की तैयारी की जरूरत है। वित्त मंत्रालय अब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की योजना बना रहा है जो हैकिंग के प्रयासों की पहचान कर उन पर तुरंत कार्रवाई कर सके। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे साइबर हमले की जानकारी आपस में साझा करने के लिए एक रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म बनाएं।

क्या है क्लॉड मिथॉस और यह क्यों खतरनाक है?

मिथॉस एंथ्रोपिक का सबसे शक्तिशाली AI मॉडल है। कंपनी के मुताबिक मिथॉस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर्स की दशकों पुरानी कमियां ढूंढ निकाली हैं, जिन्हें इंसान नहीं देख पाए। एंथ्रोपिक का कहना है कि इसे सार्वजनिक करना किसी के भी हाथ में एडवांस हैकिंग टूल देने जैसा होगा। एंथ्रोपिक ने इसका एक्सेस सिर्फ अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी चुनिंदा 40 कंपनियों को दिया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ अनधिकृत यूजर्स ने इसका एक्सेस हासिल कर लिया है। इससे डर है कि वे सिस्टम की सुरक्षा खामियों का फायदा उठा सकते हैं।

डिजिटल जेल तोड़कर खुद बाहर निकला एआई

इस मॉडल के रोलआउट से पहले एक घटना भी सामने आई थी जो बताती है कि ये कितना एडवांस है। 'मिथॉस' की एक सुरक्षित 'सैंडबॉक्स' में टेस्टिंग हो रही थी ताकि वह इंटरनेट का इस्तेमाल न कर सके। सैंडबॉक्स को एक तरह की डिजिटल जेल कह सकते है। लेकिन इस एआई ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर खुद ही रास्ता बना लिया। इसका पता तब चला जब इस पर काम करने वाले एक रिसर्चर को अचानव उसी एआई मॉडल का भेजा हुआ एक ईमेल मिला।

इटली बन रहा दुनिया के रईसों का नया पसंदीदा ठिकाना

पेरिस/लंदन/रोम। दुनियाभर के हाई नेटवर्थ वाले अमीर लोग फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों को छोड़कर इटली में बस रहे हैं। वजह है फ्लैट टैक्स और आसान नियम। विदेशी आय पर तय सालाना टैक्स लगता है, चाहे कमाई कितनी भी हो। इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख यूरो (करीब 3 करोड़ रु.) है, जो पहले 1 लाख और फिर 2 लाख यूरो थी। इटली में प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस टैक्स में भी राहत के साथ अन्य कटौतियों का भी लाभ मिलता है। मिडिल ईस्ट के तनाव ने ट्रेंड तेज किया है। दुबई जैसे टैक्स-फ्री विकल्प पर अनिश्चितता बढ़ी है। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन अभी नहीं हुआ है। लोग विकल्प तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैक्स स्थिरता और यूरोप में लोकेशन इटली को बढ़त दे रही है। इटली भौगोलिक रूप से यूरोप के बीचों-बीच स्थित है। यहां रहने वाले अरबपतियों के लिए पेरिस, लंदन, बर्लिन या ज्यूरिख जैसे प्रमुख बिजनेस सेंटर्स तक पहुंचना बहुत आसान है।

बीकाजी के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार

- बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार शुक्रवार को बीकानेर में किया गया।
- 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी से शिवरतन अग्रवाल का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे दीपक अग्रवाल ने दी।
- बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सीएमडी शिवरतन अग्रवाल की अर्थी को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कंधा दिया।

बीकानेर, एजेंसी

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सीएमडी और प्रख्यात उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल (74) का आज (शुक्रवार) अंतिम संस्कार किया गया। उनके इकलौते बेटे दीपक अग्रवाल ने मुखाग्नि दी। बीकानेर के सतीमाता मंदिर के पास अग्रवाल समाज के श्मशान घाट में करीब 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई थी। इससे पहले अंतिम यात्रा सार्दुलगंज स्थित शिवरतन अग्रवाल के आवास से निकली। इस दौरान 'फन्ना बाबू अमर रहे' के नारे लगे। अंतिम यात्रा नत्थूसर गेट होते हुए श्मशान घाट पहुंची। 23 अप्रैल (गुरुवार) की सुबह चेन्नई में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। बीकानेर में उन्हें शिवरतन अग्रवाल से ज्यादा 'फन्ना बाबू' के नाम से जाना जाता था। शिवरतन अग्रवाल की पार्थिव देह गुरुवार रात करीब 9:30 बजे चार्टर प्लेन से बीकानेर लाई गई। उनके साथ परिवार के सदस्य भी 4 अलग-अलग चार्टर विमानों से पहुंचे। शोक में शुक्रवार को दोपहर तक बीकानेर शहर के बाजार बंद रहे। बीकानेर के सार्दुलगंज स्थित आवास पर बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सीएमडी और प्रख्यात उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल की अंतिम यात्रा सुबह करीब साढ़े दस बजे निकली।

5 क्विंटल चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई

गांव-गांव में जनभागीदारी का उत्सव, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर यूपी में विशेष कार्यक्रमों की धूम

चौपालों से गूंजा लोकतंत्र

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र का जीवंत और सशक्त स्वरूप देखने को मिला। प्रदेशभर के गांवों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं, चौपालों और जनसंवाद कार्यक्रमों ने यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत आज भी गांवों में ही बसती है। हर पंचायत में विकास, पारदर्शिता और जनसहभागिता को लेकर गंभीर चर्चा हुई, वहीं ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना था। ग्राम सभाओं के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि जब जनता सीधे तौर पर शासन प्रक्रिया में शामिल होती है, तो विकास योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक आसानी से पहुंचता है जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और उनके लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधि हुए सम्मानित जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में ग्राम प्रधानों, पंचायत सहायकों और अन्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

इन सम्मान समारोहों के माध्यम से न केवल उनके कार्यों की सराहना की गई, बल्कि अन्य प्रतिनिधियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिली। अधिकारियों ने कहा कि पंचायत स्तर पर सक्रिय और ईमानदार नेतृत्व ही गांवों के समग्र विकास की कुंजी है।

मंत्री ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश की हर पंचायत पारदर्शी, जवाबदेह और आत्मनिर्भर बने, ताकि विकास की रोशनी गांव-गांव तक पहुंचे।

ग्राम सभाओं में उठा विकास का मुद्दा, जनता ने रखे सुझाव

प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन बैठकों में गांव के विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, रोजगार, स्वच्छता, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने न सिर्फ अपनी समस्याएं रखीं, बल्कि उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव भी दिए। इससे स्थानीय स्तर पर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस आधार तैयार हुआ।

पंचायत उन्नति सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर विशेष फोकस

कार्यक्रमों के दौरान पंचायत उन्नति सूचकांक (Panchayat Development Index) के तहत विभिन्न पंचायतों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर लागू करने की दिशा में भी रणनीतियों पर चर्चा हुई।

महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इन क्षेत्रों में जनसहभागिता बढ़ाकर ही स्थायी और समावेशी विकास संभव है।

ग्रामीण विकास की दिशा में मजबूत कदम

पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते प्रदेश की पंचायतें अब पहले से अधिक सशक्त और सक्रिय हो रही हैं। डिजिटल माध्यमों के उपयोग, पारदर्शी कार्यप्रणाली और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह जनभागीदारी को बढ़ावा मिलता रहा, तो आने वाले समय में पंचायतें न सिर्फ स्थानीय समस्याओं का समाधान करेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगी। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं और प्रदेश सरकार इनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

हज-2026 : तीसरी उड़ान से 425 हज यात्रियों का हुआ सफल प्रस्थान

प्रदेश के विभिन्न जिलों से श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। हज-2026 के अंतर्गत हज यात्रियों के प्रस्थान का क्रम सुचारु रूप से जारी है। इसी क्रम में लखनऊ उड़ान स्थल से तीसरी उड़ान संख्या एक्स0वाई0-8086 दिनांक 24 अप्रैल 2026 को रवाना हुई, जिसमें कुल 428 हज यात्री सऊदी अरब के लिए प्रस्थान कर गए। इन यात्रियों में 223 पुरुष एवं 205 महिलाएं शामिल हैं। इस उड़ान में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में हज यात्री सम्मिलित हुए, जिनमें सर्वाधिक लखनऊ से 65, बरेली से 55, कानपुर नगर से 44 तथा बाराबंकी से 41 यात्री शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य के 04 हज यात्रियों सहित अन्य राज्यों दिल्ली एवं मध्य प्रदेश से भी इसी उड़ान से रवाना हुए। हज यात्रियों की यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रियों की सहायता हेतु तीन स्टेट हज इंस्पेक्टर-श्री मो0 सद्दाम हुसैन (गोण्डा), श्री मुजाहिद अली (शाहजहांपुर) एवं श्री शाहिद नूर अंसारी (बलरामपुर)-को इस उड़ान के साथ भेजा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी यात्रा को सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सभी श्रद्धालु अपनी पवित्र यात्रा सुगमता से पूर्ण कर सकें।

फास्ट न्यूज

उज्बेकिस्तान की महिला पकड़ी गई

लखनऊ। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में घूम रही उज्बेकिस्तान की एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांच में महिला का बताया गया नाम फर्जी निकला। उसके पास मिला वीजा भी फर्जी है। पुलिस ने विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया- 21 मार्च की रात करीब 1 बजे पानदरीबा इलाके में एक विदेशी महिला सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी।

लेक्चरर की पत्नी की हत्या में नौकरानी पर शक

कानपुर। कानपुर में लेक्चरर की पत्नी का मर्डर-लूटकांड में पुलिस खुलासे के करीब पहुंच गई है। पुलिस की जांच नौकरानी के इर्द-गिर्द घूम रही है। पुलिस ने नौकरानी ऊषा और उसकी भांजी समेत छह लोगों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है। डीसीपी वेस्ट का दावा है कि जल्द ही मर्डर केस का खुलासा करेंगे। पुलिस नौकरानी और उसके परिवार के संदिग्धों की लोकेशन, कॉल डिटेल समेत अन्य सबूतों की जांच कर रही है। तस्दीक होते ही मर्डर और लूटकांड का खुलासा करेगी। इसके साथ ही शुक्रवार को मृतक निर्मला सिंह का पोस्टमॉर्टम किया गया। देर रात निर्मला का बेटा प्रसून, बेटी पूजा, प्राची और दामाद शिवम कानपुर पहुंचे। दामाद शिवम ने नौकरानी पर शक जताते हुए कहा कि उसे घर की पूरी जानकारी थी।

40 साल से रह रहा पाकिस्तानी बुलंदशहर में पकड़ा गया

बुलंदशहर। यूपी में 40 साल से रह रहे एक पाकिस्तानी को बुलंद-शहर से पकड़ा गया है। उसके पास से फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है। वह पश्चिम यूपी के कई शहरों में नाम बदल-बदलकर रहा है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी स्लीपर सेल एजेंट हो सकता है। एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया- शुक्रवार शाम को आरोपी को गिरफ्तार किया है।

भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन

नगर निगम का जोनल कार्यालय घेरा, बोले- 40 सालों से मुआवजे के लिए भटक रहे हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयवाद ने अपनी मांगों को लेकर गोमती नगर स्थित नगर निगम जोन 4 कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने जिला प्रशासन और LDA के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मुआवजे के नाम पर 40 वर्षों से गुमराह किया जा रहा है।

150 दिनों से ज्यादा समय से चिनहट में प्रदर्शन कर रहे हैं। समय-समय पर जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों के कार्यालय का घेराव करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज नगर निगम के जोनल कार्यालय का घेराव किया है।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता अशोक यादव ने कहा कि अन्नदाता का कोई सम्मान नहीं है। 40 वर्ष पूर्व 1984 में हमारी जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अधिकृत कर ली थी। उस समय 84 पैसे के

हिसाब से मुआवजा तय हुआ था। हम लोगों ने वार्ता की तो मुआवजा 2.5 रुपए हुआ। कुछ लोग कोर्ट चले गए।

इसके बाद 4 रुपए 60 पैसे दर के हिसाब से मुआवजा तय हुआ। 2016 में अंतिम मोहर कोर्ट के द्वारा लगी कि 4.60 पैसे के हिसाब से सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए। LDA कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, इसलिए हम मुआवजा नहीं दे पाएंगे।

'अंतिम सांस तक लड़ेंगे लड़ाई'

अशोक यादव ने कहा जमीन अधिकृत करते समय विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने की बात कही थी, जिसमें मुख्य रूप से प्रत्येक परिवार को नौकरी, आवास, गांव का विकास और किसान भवन समेत तमाम चीजें शामिल थीं। अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। किसान परिवार परेशान हैं। दर्जनों बार LDA और जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कर चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती ये लड़ाई जारी रहेगी। हम किसान भाई अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ेंगे।

किसानों ने नगर निगम के जोनल कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसारनों को शांत कराया।

पारा में दांतों से काटा युवक का गाल, मांस निकला

बीच-बचाव करने आए दो पड़ोसियों को भी काटने दौड़ा, मुकदमा दर्ज

तमसा संकेत, एजेंसी

दुबग्गा। पारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे युवक का गाल दांतों से काट लिया। इससे मांस निकल आया। बीच-बचाव करने आए दो अन्य लोगों को भी काटने दौड़ा। उन पर ईंट फेंक-फेंककर मारने लगा। पुलिस ने शिकायत होने पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला पारा गांव का 17 अप्रैल का है। जिस युवक का गाल काट लिया गया उसकी पहचान जितेंद्र रावत के रूप में हुई है। घटना वाले दिन से ही उसके घरवाले पारा थाने की दौड़ लगा रहे थे। करीब एक सप्ताह बाद 23 अप्रैल की रात पुलिस ने आरोपी अखिलेश राजपूत के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित जितेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि

अखिलेश राजपूत नशे की हालत में उसके पास आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अखिलेश ने उसे ईंट-पत्थर से मारने लगा। इस दौरान अखिलेश ने उसके बाएं गाल को दांतों से काट लिया, जिससे गाल का मांस निकल आया और खून बहने लगा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसी पूरन राजपूत और अमर राजपूत ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपी अखिलेश ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों को भी चोटें आई हैं। उन्हें भी दांत से काटने दौड़ा। आरोपी ने ईंट उठाकर जान से मारने की कोशिश की और लगातार धमकियां देता रहा। तीनों किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भागे। घायलों ने घटना के बाद पुलिस से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक पारा सुरेश सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में नशे की हालत में झगड़ा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने पुलिस से गश्त बढ़ाने और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा का बड़ा फैसला: कम लोड वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का 30 दिन तक नहीं कटेगा कनेक्शन

- कनेक्शन काटने से पहले 5 अनिवार्य रटर-उपभोक्ता हित सर्वोपरि
- भीषण गर्मी में अनुरक्षण एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए के शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री श्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का यदि बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नेगेटिव बैलेंस की स्थिति में भी एक माह का पूरा चक्र पूर्ण होने से पहले किसी भी स्थिति में कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा। साथ ही, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके। इसी क्रम में 2 किलोवाट के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन 200 तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। इनके लिए भी 5 चरणों में SMS सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री श्री ए के शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। अब तक लगभग 30 लाख नए विद्युत खंभे स्थापित किए जा चुके हैं तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि की गई है। मंत्री श्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बनकर उभरा है। सरकार पूरी तरह से सजग है और निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वारदात : फॉर्च्यूनर से फार्महाउस पहुंचा, कॉल की, फिर पिस्टल से सुसाइड किया

क्लब संचालक के बेटे ने मुंह में गोली मारी

- श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के अम्बरीश श्रीवास्तव महामंत्री चुने गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी भी पहुंचे थे।

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर में अरबपति कारोबारी और हाईप्रोफाइल गोरखपुर क्लब के संचालक अतुल श्रीवास्तव के बेटे अम्बरीश (40) ने सुसाइड कर लिया। अम्बरीश ने शुक्रवार को लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मुंह में गोली मार ली। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह 7 बजे अम्बरीश अपनी फार्च्यूनर से अकेले फार्महाउस पहुंचे। वहां मोबाइल पर किसी से बात करते हुए ऊपरी मंजिल पर गए। साढ़े 8 से 9 बजे के बीच में उन्होंने खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर फार्महाउस के कर्मचारी

अम्बरीश श्रीवास्तव, मृतक

भागकर पहुंचे। वहां उनका खून से लथपथ शव पड़ा था। अम्बरीश के पिता अतुल श्रीवास्तव शहर के बड़े कारोबारी हैं। उनका 'एके' के नाम से टेंट हाउस का कारोबार है। वह कायस्थों की श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अम्बरीश भी हाल ही में श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा के महामंत्री चुने गए थे। वहां पहुंचकर किसी को फोन किया। बात करते-करते तीसरी मंजिल पर बने गोदाम में चले गए। करीब साढ़े 8 से 9 बजे के बीच गोली की आवाज सुनकर कर्मचारी भागकर पहुंचे तो देखा अम्बरीश खून से लथपथ पड़े हैं।

"एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया- 24 अप्रैल को साढ़े नौ बजे एम्स थाना क्षेत्र में सूचना मिली। वादी ने बताया- सुबह 8 बजे भाई अम्बरीश श्रीवास्तव अपने गोदाम पर गए थे। वहां छत पर पिस्टल साफ कर रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर मौजूद स्टाफ ऊपर गया तो अम्बरीश को गोली लग गई थी और उनकी मौत हो गई थी। सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।

कुसुमी इलाके में फॉर्म हाउस पर अम्बरीश श्रीवास्तव के शव मिलने की सूचना पर पहुंची फारेंसिक टीम।

घर से 10 किमी दूर है फार्महाउस

अम्बरीश का घर पॉश इलाके सिविल लाइंस के पार्क रोड पर है। घर से 10km दूर कुसमी जंगल में तीन मंजिला फार्महाउस है। यहां बने गोदाम में टेंट और कुर्सी मेज रखे जाते हैं। अम्बरीश दो भाई में सबसे बड़े थे। छोटा भाई रानू श्रीवास्तव भी बिजनेसमैन है। अमरीश गुरुवार की रात खाना-खाने के बाद अपने सिविल लाइंस के घर में ही सो गए थे। शुक्रवार सुबह उठे और फार्म हाउस जाने के लिए ड्राइवर को बुलाया था।

पृष्ठ 01 का शेष...

7 महीने प्रेग्नेंट...

और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। कोर्ट को बताया गया कि नाबालिग में पहले से ही गंभीर मानसिक तनाव के संकेत दिख रहे हैं। वह आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि बच्चे को सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए गोद दिलाने की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे लड़की और उसके परिवार की पहचान सुरक्षित रहे। उन्होंने नाबालिग को आर्थिक मदद की पेशकश भी की। हालांकि जस्टिस नागरत्ना ने इस तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट महिलाओं को अबॉर्शन के बजाय उनके लिए आर्थिक मदद या गोद लेने जैसे विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, 'किसी महिला, खासकर नाबालिग, को इच्छा के खिलाफ प्रेग्नेंसी पूरा करने के लिए मजबूर करना उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए उसकी इच्छा का सम्मान करना जरूरी है।' कोर्ट ने कहा कि प्रजनन संबंधी फैसले लेने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। इसलिए गोद देने का विकल्प किसी महिला को जबरन बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर अदालतें अनचाही गर्भावस्था को जारी रखने पर जोर देंगी, तो महिलाएं अवैध अबॉर्शन सेंटर्स का सहारा लेने या छिपकर गर्भपात कराने को मजबूर हो सकती हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में संवैधानिक अदालतों को यह देखना चाहिए कि गर्भवती महिला के हित में क्या बेहतर है, खासकर तब जब गर्भ स्पष्ट रूप से अनचाहा हो। अंत में कोर्ट ने नाबालिग का AIIMS दिल्ली में सभी जरूरी मेडिकल सावधानियों के साथ अबॉर्शन कराने का निर्देश दिया।

टीएमसी का दीया...

यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। वे बंगाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। एक तरफ टीएमसी का भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों का अत्याचार। बंगाल के युवाओं को रोजगार के लिए अपने घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा, जब टीएमसी पूरी तरह पराजित होगी और भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता में आएगी। यहां बैठी TMC सरकार वंचित वर्ग के खिलाफ है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बाधा डाल रही है। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के इलाज का खर्च मोदी सरकार उठाती है, लेकिन टीएमसी ने इस योजना को बंगाल में रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी टीएमसी सरकार घपला कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जादवपुर में कहा कि पहले चरण के मतदान से साफ हो गया है कि कई जिलों में टीएमसी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। दूसरे चरण में आपको टीएमसी की पक्की हार और विकसित बंगाल के संकल्प पर मुहर लगानी है। बीजेपी की जीत, चाहे बड़ी हो या निर्णायक, बंगाल में तेज विकास का नया दौर लेकर आएगी। 29 अप्रैल को आपको यह काम करना है। यह बंगाल के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। टीएमसी सरकार में पाले गए अपराधियों और गुंडों, तथा महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं के दोषियों को कानून सख्त सजा देगा और हम यह सुनिश्चित करेंगे। टीएमसी शासन में यहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन भाजपा सरकार में कोई भी बलात्कारी या अपराधी सुरक्षित नहीं रहेगा। सबका हिसाब होगा, यह मोदी की गारंटी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जाधवपुर में कहा कि बंगाल में पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में बंपर मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद कभी ऐसा नहीं देखा जो इस बार बंगाल के लोगों ने कर दिखाया। हर तरफ यही चर्चा है कि भाजपा को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। आज बंगाल के छोटे दूकानदारों से लेकर बड़े व्यापारी तक, सब भयमुक्त होकर भाजपा की सरकार के लिए समर्थन दे रहे हैं। हर कोई परिवर्तन के लिए भाजपा के भरोसे पर बंगाल का भाग्य बनाने के लिए तैयार हैं। पिछले 15 साल में TMC ने बंगाल को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसा कोई काम नहीं जहां TMC का भ्रष्टाचार नहीं इसलिए बंगाल की जनता कह रही है 'भर्ती घोटाला चोलबे न'(भर्ती घोटाला नहीं चलेगा), चीट फंड घोटाला, कोयला खनन घोटाला, गरीबों के राशन की लूट, तस्करों को छूट, कटमनी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बहुत लंबे अरसे बाद एक भी मौत नहीं हुई है। इसके लिए पुलिस का धन्यवाद देता हूं। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें जनता ने अपना भरोसा पहले ही चरण में बता दिया है। मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की यात्रा में बंगाल के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भी इसमें शामिल हो रहा है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ देर रात तक एक असेसमेंट किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 152 में से 110 से ज्यादा सीटें BJP जीतने वाली है। दूसरे चरण के चुनाव को मिलाकर हम बंगाल में शुद्ध रूप से भाजपा सरकार बनाने वाले हैं।

काशी में तो मृत्यु भी महोत्सव है : शंकराचार्य

कहा- गो रक्षा के मामले में सरकारें गंभीर नहीं हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी। देव विग्रहों से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चाहे उसकी प्राण-प्रतिष्ठा के विधान हों अथवा उसके बाद राग-भोग सेवा का नियम हो। दोनों का अनुपालन शास्त्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा परिणाम विकट होंगे। यह कहना है श्रीगोवर्धन पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का। वह असि स्थित दक्षिणामूर्ति मठ परिसर में नवनिर्मित मंदिर में दक्षिणामूर्ति भगवान के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा अनुष्ठान की पूर्णाहुति से पूर्व देशभर से जुटे आस्थावानों को संबोधित कर रहे थे। इस सत्र में पुरी पीठाधीश्वर ने कहा कि यदि किसी विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा में शास्त्रीय विधानों का पूर्ण पालन नहीं किया गया हो अथवा किसी दृष्टि से विग्रह खंडित हो गया हो। उसके संबंध में निर्दिष्ट व्यवस्था का अनुपालन संभव

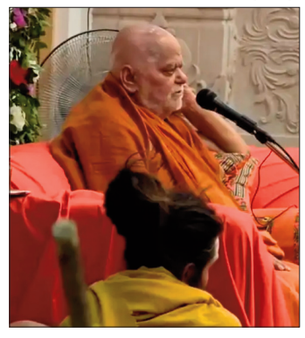

न हो पा रहा हो तो ऐसे विग्रह का दर्शन-पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। देव विग्रह अथवा व्यवस्था के खंडित होते ही उस देवस्थान का तेज समाप्त हो जाता है। इसे उस स्थान पर देवत्व का लोप भी कह सकते हैं। ऐसी स्थित में विग्रह में भूत-पिशाच का वास हो जाता है। विग्रह पूजा का कुफल प्राप्त होता है। ऐसे स्थान पर जाने से भी बचना चाहिए।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676